by the Department of Industrial Policy and Promotion.

(f) The Government helps sugar mills to improve their working by availing of wjicessional finance from Sugar development Fund for rehabilitation, modernisation and upgradation of capacitv. Upto 30.6.97, 166 sugar mills iuid been sanctioned loans from Sugar Development Fund amounting to Rs. 609.17. crores. Besides, 355 units were also sanctioned Cane Development Loans amounting to Rs. 485.22 crores.

Statement

S.No.	State	No. of Applications pending
1.	Madhya Pradesh	24
2.	Maharashtra	13
3.	U.P.	73
4.	Punjab	3
5.	Nagaland	1
6.	Himachal Pradesh	1
7.	Tamil Nadu	7
8. .	Karnataka	12
9.	Andhra Pradesh	12
10.	Pondicherry	1
11.	Jammu & Kashmir	1
12.	Haryana	2
	Total	150

Sub-Standard Sugar Diverted to Mumbai for sale in Open Market

494. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Merchant essel carrying about 1000 tonnes of sub-standard sugar which was rejected by the Lankan authorities was diverted to the Mumbai harbour for unloading its cargo for sale of sugar in the open market; and

(b) if so, the details thereof and the ..isons iherefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANS PRASAD SINGH): (a) and (b) A consignment of 1335 tonnes of sugar was brought to Mumbai port on MV Natalie on 13.4.1997. The consignment was unloaded from MV Natalie in stream into barge 'Prosper' under customs permission and supervision on 15.5.1997. The barge has been at berth in Prince's Dock from 12.6.97. As per the certificate issued Food and Drug Administration, Government of Maharashtra, the sugar is moist, stick with fermented shell and hence unfit for human consumption. The sugar is still lying loaded on the barge awaiting disposal.

Strengthening the infrastructure of Consumer Courts

495. SHRI SANIAY NIRUPAM:
SHRI MUKESH R. PATEL:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had granted financial assistance to the State Governments for strengthening the infrastructure of Consumer Courts;

(b) whether it is also a fact that Maharashtra Government could not utilise the allocated fund for this; and

(c) if so, whether State Government has requested Central Government to consider the reallocation of financial assistance for strengthening the infrastructure of Consumer Courts?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANS PRASAD SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. Request of the Maharashtra Government regarding

invalidation of the unutilised grant has been duly approved by the Central Government. 10

किलोग्राम अनाज प्रदान करने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

496. **प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या खाध और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आधे मूल्य पर प्रति परिवार 10 किलोग्राम अनाज प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) सस्ते मूल्य पर दिए जा रहे अनाज की राज्य-वार दर क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों में उक्त योजना लागू नही की गई है और इसके क्या कारण है?

खाध तथा उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रतिमास 10 किलोग्राम खाधान्न देने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना पंजाब, दिल्ली, गोवा और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यन्वित कर दी गई है ।

(ख) इस योजना के अधीन लाभान्वित होने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की राज्यवार संख्या विवरण – 1 में दी गई है । (**नीचे देखिए**)

(ग) खाधान्नों के निर्गम मूल्यों का राज्यवार ब्यौरा दिए गए विवरण – II में दिया गया है ।

(घ) यह योजना पंजाब, दिल्ली और गोवा के राज्यों तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में आरम्भ नही की गई है । ये राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर रहे है जिनमें गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, सतर्कता समितियां गठित करना, आदि शामिल है ।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभान्वित होने वाले गरीब रेखा से नीचे के परिवारों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)
आंध्र प्रदेश	32.35
अरूणाचल प्रदेश	0.74
असम	19.06
बिहार	85.90
गोवा	0.38
गुजरात	19.95
हरियाणा	7.33
हिमाचल प्रदेश	2.96
जम्मू कश्मीर	3.80
कर्नाटक	28.75
केरल	15.35
मध्य प्रदेश	53.34
महाराष्ट्र	60.45
मणिपुर	1.08
मेघालय	1.33
मिजोरम	0.33
नागालैण्ड	0.88
उडीसा	31.82
पंजाब	4.30
राजस्थान	21.66
सिकिम्म	0.34
तमिलनाडु	45.79
त्रिपुरा	2.21
उत्तर प्रदेश	95.48
पश्चिम बंगाल	46.59
दिल्ली	2.96
अंडमान और निकोबार	0.22
चण्डीगढ़	0.18
दादर और नगर हवेली	0.14
लक्षद्वीप	0.02
पांडिचेरी	0.65
जोड़	586.64